विचार बिन्दु

जहाँ नक़ल है वहां खाली दिखावट होगी, जहाँ खाली दिखावट है वहां मूर्खता होगी। –जॉन्सन

आधारभूत संरचनाओं से सँवर रहा राजस्थान

राजस्थान केवल अपने किलों, महलों, रेगिस्तान और सांस्कृतिक विरासत के लिए ही जाना जाता नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में यह तेजी से बदलती आधारभूत संरचना के कारण भी एक नई पहचान बना रहा है। किसी राज्य का समग्र विकास उसकी सड़कों, रेलमार्गों, ऊर्जा, जल, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी सुविधाओं तथा डिजिटल ढांचे पर निर्भर करता है। राजस्थान जैसे विशाल और भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण राज्य में इन सुविधाओं का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के विकास में रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र, दूरस्थ गाँव और विरल जनसंख्या जैसी बाधाएँ भी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा सड़क, रेल, ऊर्जा, जल, पर्यटन, औद्योगिक विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास राजस्थान को एक आधुनिक, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य की ओर ले जा रहे हैं। आधारभूत संरचना का विकास केवल ईंट-पत्थर का निर्माण नहीं है, बल्कि यह जनजीवन की गुणवत्ता, रोजगार, निवेश, शिक्षा और सामाजिक न्याय का आधार भी है।

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका विस्तार थार मरुस्थल से लेकर अरावली पर्वतमाला तक फैला हुआ है। ऐसे विशाल क्षेत्र में हर गाँव, कस्बा और शहर को मुख्य धारा से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती का सामना करने के लिए राज्य में सड़क नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य सड़कें, ग्रामीण सड़कें और ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मार्गों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन बदल रहा है। अच्छी सड़कों से किसान अपनी उपज को समय पर मंडियों तक पहुँचा पा रहे हैं, विद्यार्थी स्कूल और कॉलेज तक आसानी से पहुँच रहे हैं तथा मरीज आपातकाल में अस्पताल तक पहुँचने में सक्षम हो रहे हैं। सड़कों के विस्तार ने न केवल यातायात को सुगम बनाया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति दी है।

राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बाईपास, फ्लाईओवर और चौड़ीकरण परियोजनाओं से परिवहन व्यवस्था में सुधार आया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले मार्गों के उन्नयन से व्यापार और पर्यटन को लाभ हुआ है। विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में सड़क संपर्क का महत्व अधिक है, क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान लगातार बढ़ रहा है। जयपुर से आगरा, दिल्ली, उदयपुर और जोधपुर जैसे मार्गों पर सुधार से पर्यटकों की सुविधा बढ़ी है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पहुँच से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। एक विकसित सड़क व्यवस्था राज्य की अर्थव्यवस्था की रक्त नसों के समान है, जो वस्तुओं, सेवाओं और लोगों के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है।

रेल परिवहन भी राजस्थान की आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों को देश के प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों से जोड़ने में रेलवे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और उदयपुर जैसे शहर रेल मार्गों से देश के विभिन्न भागों से जुड़े हुए हैं। रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण, दोहरीकरण और नए मार्गों के विस्तार से यात्रा का समय कम हुआ है तथा माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ी है। राजस्थान में सीमेंट, खनिज, नमक, कपास, अनाज और अन्य उत्पादों के परिवहन में रेलवे की भूमिका विशेष है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों और बेहतर स्टेशन सुविधाओं से यात्रियों को आधुनिक यात्रा अनुभव मिल रहा है। रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से दूरदराज के जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

ऊर्जा क्षेत्र राजस्थान के विकास का सबसे चमकता पहलू बन चुका है। राज्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और पाली जैसे जिलों में प्रचुर सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होने से सौर ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावनाएँ हैं। राजस्थान में बड़े सौर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं और छतों पर सौर पैनल लगाने को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मार्च 2024 तक राज्य की स्थापित ऊर्जा क्षमता लगभग 24,783 मेगावाट थी, जिसमें तापीय, पवन, सौर और अन्य नवीकरणीय स्त्रोतों का योगदान शामिल है। राज्य में पवन ऊर्जा के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जिससे जैसलमेर और जोधपुर क्षेत्र में बड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाएँ विकसित हुई हैं।

ऊर्जा के विस्तार ने राजस्थान के ग्रामीण जीवन को भी बदला है। बिजली की नियमित आपूर्ति से गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और छोटे उद्योगों को बल मिला है। किसानों के लिए सौर पंपों की उपलब्धता से सिंचाई अधिक सुलभ हुई है। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप न केवल डीजल पर निर्भरता कम करते हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी सहायक हैं। राज्य सरकार सार्वजनिक भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिससे ऊर्जा खपत में कमी और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान की ऊर्जा नीति यह संदेश देती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं।

जल संरचना राजस्थान की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यह अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों वाला राज्य है। यहाँ वर्षा असमान और सीमित होती है, इसलिए जल संचयन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान के जीवन को बदल दिया है। इस नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जैसे जिलों में सिंचाई के अवसर बढ़े तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषि को नया जीवन मिला। नहर के विस्तार और रखरखाव से किसानों को सिंचाई सुविधा मिल रही है और खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में बांधों, तालाबों, अनीकटों, खड़िनों और जल जीवन मिशन जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण पर बल दिया जा रहा है।

राजस्थान अब केवल अतीत की विरासत का राज्य नहीं है, बल्कि भविष्य की ओर तेजी से बढ़ता हुआ आधुनिक राज्य बन रहा है। सौर ऊर्जा की अगुवाई, बेहतर सड़कों, विस्तारती रेल संपर्क, जल प्रबंधन और डिजिटल क्रांति से राजस्थान का स्वरूप बदल रहा है। यदि विकास की यह गति निरंतरता, गुणवत्ता और समावेशिता के साथ आगे बढ़ती है, तो राजस्थान निश्चित रूप से एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में उभरेगा।

पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों का महत्व राजस्थान में आज भी उतना ही है, जितना प्राचीन काल में था। बावड़ियाँ, तालाब, जोहड़ और खड़िन जैसी संरचनाएँ न केवल जल संग्रह का साधन हैं, बल्कि ये स्थानीय समाज की पारिस्थितिक समझ का भी प्रतीक हैं। आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान के संयोग से राज्य में जल संकट के समाधान की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से दूरस्थ गाँवों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने का कार्य जारी है। जल की उपलब्धता से स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और महिलाओं की दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ती है। इस प्रकार जल आधारित बुनियादी ढाँचा राजस्थान के मानव विकास का आधार है।

शहरी आधारभूत संरचना के विकास से भी राजस्थान का स्वरूप बदल रहा है। जयपुर मेट्रो, शहरी सड़कों का चौड़ीकरण, स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति और सार्वजनिक परिवहन जैसी पहलों से शहरी जीवन में सुधार आया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जैसे शहरों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के अंतर्गत सड़कें, वेस्ट मैनेजमेंट, सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और नागरिक सेवाओं में तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। शहरी विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और निवेशकों का आकर्षण भी बढ़ता है।

औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना अनिवार्य है। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र और निवेश को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों से उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। सीमेंट, खनिज, टेक्सटाइल, जूते, हस्तशिल्प, मार्बल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अच्छी सड़कें, बिजली, पानी और संचार सुविधाएँ उद्योगों को स्थापित होने और विकसित होने में सहायक होती हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और गुजरात के व्यापारिक मार्गों से जोड़ती है, जिससे इसे व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल बनाती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी संरचना भी राजस्थान के समग्र विकास में महत्वपूर्ण है। स्कूल भवनों, कॉलेजों, आईटीआई, विश्वविद्यालयों और कौशल विकास केंद्रों के विस्तार से युवाओं को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच बढ़ाने के लिए नए स्कूल भवन, डिजिटल कक्षाएँ और छात्रवृत्ति योजनाएँ सहायक सिद्ध हो रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मोबाइल मेडिकल यूनिटों का विस्तार किया जा रहा है। बेहतर स्वास्थ्य ढाँचे से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार का अवसर मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश दीर्घकालिक मानव पूँजी निर्माण करता है, जो राज्य के भविष्य का आधार है।

पर्यटन आधारभूत संरचना का विकास राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राजस्थान में किले, महल, हवेलियाँ, झीलें, वन्यजीव अभयारण्य और धार्मिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़कें, होटल, पार्किंग, स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालय, सूचना केंद्र और डिजिटल बुकिंग सुविधाओं का विकास आवश्यक है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और पुष्कर जैसे स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं के सुधार से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। पर्यटन से हस्तशिल्प, कला, संगीत, खाद्य उद्योग और परिवहन क्षेत्र को भी लाभ होता है। इस प्रकार पर्यटन आधारित संरचना सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों का सेतु बनती है।

राजस्थान के विकास में ग्रामीण आधारभूत संरचना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राम सड़कें, पेयजल, बिजली, स्कूल, उपचार केंद्र, पंचायत भवन और डिजिटल सेवाएँ गाँवों के विकास की नींव हैं। ग्रामीण सड़कों के विस्तार से किसानों को बाजार तक पहुँच मिली है। पेयजल परियोजनाओं से महिलाओं को दूर तक पानी लाने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। सौर ऊर्जा से गाँवों में रात के समय भी रोशनी और डिजिटल संपर्क संभव हुआ है। ग्रामीण विकास से पलायन कम होता है और गाँवों में ही रोजगार के अवसर बनते हैं। इसलिए ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास सामाजिक समानता और संतुलित विकास के लिए आवश्यक है।

फिर भी चुनौतियाँ हैं। राजस्थान के विशाल क्षेत्र में सभी क्षेत्रों तक समान गुणवत्ता की सुविधाएँ पहुँचाना कठिन है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल की कमी, गर्मी, रेत और दूरी जैसी समस्याएँ बनी रहती हैं। कुछ क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता, बिजली आपूर्ति की निरंतरता, शिक्षकों और डॉक्टरों की उपलब्धता तथा डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार की आवश्यकता है। बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में वित्तीय संसाधन, समयबद्ध कार्यान्वयन और गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। साथ ही विकास के दौरान पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना भी आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान की पारिस्थितिकी संवेदनशील है।

आगे के विकास के लिए राजस्थान को टिकाऊ और समावेशी आधारभूत संरचना की दिशा में बढ़ना होगा। सौर और पवन ऊर्जा के विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण और ग्रिड सुधार पर ध्यान देना आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन, नहरों का आधुनिकीकरण और भूजल प्रबंधन आवश्यक है। सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए। डिजिटल सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाना, स्थानीय भाषा में जानकारी उपलब्ध कराना और महिलाओं तथा दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करना आवश्यक है। शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार से ही आधारभूत संरचना का वास्तविक लाभ जनता तक पहुँचेगा।

अंततः कहा जा सकता है कि आधारभूत संरचना राजस्थान के विकास की रीढ़ है। सड़कें, रेलमार्ग, ऊर्जा, जल, डिजिटल नेटवर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी सुविधाएँ मिलकर राज्य को एक नई पहचान दे रही हैं। राजस्थान अब केवल अतीत की विरासत का राज्य नहीं है, बल्कि भविष्य की ओर तेजी से बढ़ता हुआ आधुनिक राज्य बन रहा है। सौर ऊर्जा की अगुवाई, बेहतर सड़कों, विस्तारती रेल संपर्क, जल प्रबंधन और डिजिटल क्रांति से राजस्थान का स्वरूप बदल रहा है। यदि विकास की यह गति निरंतरता, गुणवत्ता और समावेशिता के साथ आगे बढ़ती है, तो राजस्थान निश्चित रूप से एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में उभरेगा। आधारभूत संरचनाओं से सँवरता राजस्थान न केवल अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन का सपना दिखा रहा है, बल्कि पूरे देश के सामने संतुलित और टिकाऊ विकास का उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

जयपुर का ज्वेलरी और नगीना कारोबार : हुनर की चमक से दुनिया को रोशन करता गुलाबी नगर

जैपुर - तीन सदियों का गुलाबी सफ़र.....



डॉ. गोरधन लाल शर्मा

पन्ने की चमक, कुंदन-मीनाकारी का वैभव और जड़ाऊ आभूषणों की बेजोड़ कारीगरी... रामलला के दिव्य श्रृंगार से विश्व कप ट्रॉफी तक, जयपुर के हुनर ने दुनिया में बनाई विशिष्ट पहचान।

गुलाबी नगरी जयपुर की पहचान उसके भव्य महलों, ऐतिहासिक इमारतों और स्थापत्य वैभव तक सीमित नहीं है। इस शहर की एक ऐसी विरासत भी है, जिसकी चमक सात समंदर पार तक पहुंची है। यह विरासत है रत्नों और आभूषणों की कला। यहां साधारण पत्थर को तराशकर अनमोल नगीना बनाने से लेकर सोने पर कुंदन जड़ने और रंगों से मीनाकारी उकेरने तक, शिल्पकला का अद्भुत संसार पीढ़ियों से जीवंत है। जयपुर का जौहरी बाजार इसी हुनर, परंपरा और व्यापारिक समृद्धि का प्रतीक है। जयपुर के 299वें स्थापना दिवस की विशेष आलेख श्रृंखला में शहर की इस अनमोल विरासत को जानना एक ऐसी यात्रा है, जिसमें इतिहास, कला, व्यापार और कारीगरों का असाधारण कौशल एक साथ दिखाई देता है।

जयसिंह की दूरदृष्टि से रत्न नगरी का उदय –महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर की स्थापना करते समय इसे केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि कला, संस्कृति, ज्ञान और व्यापार का समृद्ध केंद्र बनाने की परिकल्पना की थी। इसी सोच के तहत देश के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों, कलाकारों और हुनरमंद शिल्पकारों को यहां आमंत्रित किया गया। दिल्ली, आगरा और वाराणसी सहित अनेक क्षेत्रों से आए रत्न एवं आभूषण विशेषज्ञों ने जयपुर को अपना कर्मक्षेत्र बनाया। धीरे-धीरे उनकी पारिवारिक शिल्प परंपराएं यहां के स्थानीय हुनर से जुड़कर एक विशिष्ट उद्योग में विकसित हो गईं। शहर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार और केंद्रीय चौपड़ का नाम माणक चौक रखा जाना भी इस व्यापारिक विरासत का परिचायक है। ये नाम बताते हैं कि रत्नाभूषण कारोबार जयपुर की मूल नगर परिकल्पना का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

जौहरी घरानों ने गढ़ी वैश्विक पहचान –जयपुर के रत्न कारोबार को प्रतिष्ठा दिलाने में मुकीम, मालपाणी, फोफलिया, जरगड़, संघी और अज्जा मियां जैसे प्रतिष्ठित जौहरी घरानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाद में धांधिया, बैराठी और मूसल परिवारों ने भी इस परंपरा को विस्तार दिया। लाला काशीनाथ, किशनचंद हरचंद सीघड़, रतनलाल फोफलिया, सुजानमल डाबड़ा, सुंदरलाल ठोलिया, श्रीचंद गोलेछा, गुलाबचंद बोथरा, जतनमल नौलखा और राजरूप टांक जैसे नाम इस कारोबार के इतिहास से जुड़े रहे हैं। गुजरात के मौरवी से आए विनयचंद भाई दुर्लभजी और खेलशंकर दुर्लभजी का योगदान भी उल्लेखनीय रहा।

इन परिवारों और प्रतिष्ठानों ने केवल व्यापार नहीं बढ़ाया, बल्कि पारंपरिक शिल्प को संरक्षण देकर जयपुर को अंतरराष्ट्रीय रत्न बाजार में विशिष्ट स्थान दिलाया।

पन्ने की चमक से दुनिया में पहचान –जयपुर विश्व के प्रमुख रंगीन रत्न केंद्रों में शामिल है। विशेष रूप से पन्ने की कटाई, तराश और प्रसंस्करण के लिए इसकी अंतरराष्ट्रीय पहचान रही है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कच्चे रत्न यहां पहुंचते हैं और कुशल कारीगर उन्हें अपनी कला से निखारकर आभूषणों तथा वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करते हैं। पन्ने के साथ माणक, नीलम, पुखराज, फिरोजा और अन्य रंगीन रत्नों की तराश में भी जयपुर के कारीगरों का कौशल प्रसिद्ध है।

इस उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सूक्ष्मता है। आकार, कोण और चमक में मामूली अंतर भी किसी रत्न की सुंदरता और कीमत बदल सकता है। एक रत्ती जैसे छोटे वजन में सैकड़ों बारीक नगीनों को तराशने की क्षमता यहां के कारीगरों के असाधारण हुनर का प्रमाण है। परंपरागत औजारों, पैनी दृष्टि और वर्षों के अभ्यास से विकसित यह कला आज भी जयपुर की सबसे बड़ी पूंजी है।

कुंदन-मीनाकारी में बसता है शाही वैभव –रत्नों को तराशने के साथ उन्हें आभूषणों में जड़ने की कला ने भी जयपुर को अलग पहचान दी है। यहां के कुंदन, मीनाकारी और जड़ाऊ स्वर्ण आभूषण अपनी बारीक कारीगरी, रंगों के संयोजन और पारंपरिक डिजाइन के लिए विख्यात हैं। कुंदन जड़ाई में रत्नों को सोने की सतह पर कलात्मक ढंग से स्थापित किया जाता है, जबकि मीनाकारी आभूषणों को रंगीन आकृतियों और नक्काशी से जीवंत बनाती है। इन दोनों कलाओं का संगम किसी आभूषण को संग्रहणीय कलाकृति का स्वरूप दे देता है। राजघरानों के पारंपरिक श्रृंगार से लेकर आधुनिक फैशन और भव्य विवाह समारोहों तक जयपुर के शिल्पकारों ने अपनी कला का परचम लहराया है।

रामलला के आभूषणों से विश्व कप ट्रॉफी तक – जयपुर की शिल्पकला की प्रतिष्ठा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका विस्तार धार्मिक आस्था, खेल और सिनेमा की दुनिया तक है। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के विग्रह के लिए तैयार किए गए दिव्य आभूषणों में जयपुर के प्रसिद्ध ज्वेलरी कारीगरों का योगदान इस शहर के लिए गौरव का विषय है। इसी तरह क्रिकेट विश्व कप की ट्रॉफी के निर्माण से जुड़ी जयपुर की कारीगरी ने अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में भी शहर के हुनर की छाप छोड़ी है। भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक और भव्य पृष्ठभूमि वाली चर्चित फिल्मों में कलाकारों द्वारा पहने गए राजसी आभूषणों के निर्माण में भी जयपुर के जौहरियों और कारीगरों की भूमिका रही है। इस तरह मंदिरों के दिव्य श्रृंगार से लेकर क्रिकेट के मैदान और सिनेमा के पर्दे तक जयपुर की कला अपनी विशिष्ट चमक बिखेर रही है।

राजाश्रय और संस्थागत प्रयासों ने दिया विस्तार – जयपुर के शासकों ने रत्न एवं आभूषण कारोबार को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। राजपरिवार की खरीदारी में स्थानीय जौहरियों को प्राथमिकता मिलने तथा कारोबारियों को राजकोष से ऋण उपलब्ध कराने जैसी व्यवस्थाओं ने उद्योग को मजबूती दी। नगीना तराशने वाले, जड़ाई करने वाले और मीनाकार भी इस संरक्षण से लाभान्वित हुए।

समय के साथ कारोबार को संगठित स्वरूप देने के प्रयास हुए और 1927 में ज्वैलर्स एसोसिएशन का गठन किया गया। रत्नों की शुद्धता जांचने के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं, धर्मकांटों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास हुआ। जैम एंड ज्वेलरी इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ इंडिया और जैम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जैसी संस्थाओं ने तकनीकी जानकारी, गुणवत्ता संवर्धन और निर्यात को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाई।

चुनौतियों के बीच भविष्य की नई संभावनाएं –समृद्ध विरासत के बावजूद जयपुर का रत्नाभूषण उद्योग आज कई चुनौतियों से गुजर रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आधुनिक मशीनों का बढ़ता उपयोग, कच्चे माल की उपलब्धता और बदलती बाजार मांग ने कारोबार की प्रकृति बदल दी है। थाईलैंड, श्रीलंका और इजरायल जैसे देशों ने रत्न प्रसंस्करण में तकनीकी क्षमताएं बढ़ाई हैं। वहीं सूरत जैसे शहरों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलने से जयपुर के कुछ कुशल कारीगर दूसरे क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। इससे पारंपरिक हुनर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की चुनौती भी बढ़ी है।

आवश्यकता है कि कारीगरों को आधुनिक उपकरण, कौशल प्रशिक्षण, उचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा मिले। डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, गुणवत्ता परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच के माध्यम से इस उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। ज्वेलरी हेरिटेज वॉक, शिल्प प्रदर्शन और कार्यशालाओं के भ्रमण जैसी गतिविधियां पर्यटन को भी इस विरासत से जोड़ सकती हैं।

जौहरी बाजार की चमक में छिपी है 299 साल की विरासत – जयपुर की 299 वर्षों की विकास यात्रा में रत्न और आभूषण उद्योग ऐसा अध्याय है, जिसने शहर की पहचान को वैश्विक विस्तार दिया। जौहरी बाजार की दुकानों में सजे पन्ने-माणक और कुंदन-मीनाकारी के आभूषण केवल बहुमूल्य वस्तुएं नहीं, बल्कि पीढ़ियों के अनुभव, समर्पण और कलात्मक साधना के प्रतीक हैं।

महाराजा सवाई जयसिंह की दूरदृष्टि से शुरू हुई यह यात्रा आज विश्व बाजार तक पहुंच चुकी है। जरूरत है कि इस अनमोल विरासत को अतीत का गौरव मानकर ही न छोड़ दिया जाए, बल्कि आधुनिक तकनीक, नवाचार और कुशल कारीगरों के संरक्षण के साथ भविष्य की आर्थिक शक्ति बनाया जाए। क्योंकि जयपुर की असली चमक केवल उसकी गुलाबी इमारतों में नहीं, बल्कि उन हुनरमंद हाथों में भी बसती है, जो साधारण पत्थर को नगीना और धातु को बेजोड़ कलाकृति बना देते हैं। यही हुनर दुनिया को बताता है- जयपुर की चमक सचमुच बेमिसाल है!

–डॉ. गोरधन लाल शर्मा,
समाजशास्त्री एवं राजस्थान
प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ
अधिकारी

शेनझेन में तीन महाशक्तियां : शांति की उम्मीद और भारत की कसौटी



डॉ. सुरेन्द्र सिंह

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ मुलाकातें अपने परिणामों से पहले ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चीन के शेनझेन में 19 नवंबर को प्रस्तावित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक ऐसी ही घटना है। व्हाइट हाउस की घोषणा का हवाला देने वाली खबरों के अनुसार, एपेक सम्मेलन से इतर होने वाली बातचीत में परमाणु हथियारों में कटौती और ईरान युद्ध प्रमुख विषय होंगे। हालांकि, किसी तत्काल समझौते की अपेक्षा कम है। इसलिए इसे विश्व व्यवस्था बदल देने वाले निर्णायक क्षण की जगह संवाद की संभावित शुरुआत के रूप में देखना अधिक उचित होगा।

इस बैठक का महत्व इसलिए भी है कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सैन्य अविश्वास और क्षेत्रीय युद्ध अब अलग-अलग संकट नहीं रह गए हैं। किसी समुद्री मार्ग में बाधा दुनिया भर की महंगाई बढ़ा सकती है; किसी परमाणु शक्ति की धमकी निवेश और व्यापार को प्रभावित कर सकती है। ऐसे वातावरण में तीन प्रभावशाली देशों के शीर्ष नेतृत्व का आमने-सामने बैठना उपयोगी है। लेकिन संवाद का स्वागत और उसके प्रति विवेकपूर्ण अपेक्षाएं साथ चलनी चाहिए। नेताओं की संयुक्त तस्वीर अपने आप में शांति की गारंटी नहीं होती।

परमाणु हथियारों का प्रश्न इस बातचीत की सबसे कठिन परीक्षा होगा। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है। इससे हथियार नियंत्रण की नई व्यवस्था की आवश्यकता बढ़ी है। लेकिन चीन का तर्क है कि अमेरिका और रूस के कहीं बड़े शस्त्रागारों को देखते हुए तीनों पर एक जैसा ढांचा लागू करना उचित नहीं होगा। यह मतभेद केवल हथियारों की संख्या का नहीं, सुरक्षा की परस्पर विरोधी धारणाओं का है। कोई टिकाऊ व्यवस्था इन असमानताओं को संबोधित किए बिना नहीं बन सकती।

इसलिए शेनझेन की सफलता का पहला मानदंड तत्काल बड़ी कटौती नहीं होना चाहिए। संकट के समय सीधे संवाद की व्यवस्था, गलत आकलन रोकने के उपाय, सैन्य गतिविधियों में पारदर्शिता और आगे की वार्ताओं का कार्यक्रम भी उपयोगी उपलब्धियां हो सकती हैं। परमाणु सुरक्षा केवल हथियार घटाने से नहीं आती; उन परिस्थितियों को कम करने से भी आती है जिनमें किसी तकनीकी भूल, गलत सूचना या राजनीतिक आवेश से विनाशकारी निर्णय लिया जा सकता है। घोषणाओं के साथ सत्यापन और जवाबदेही की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

ईरान युद्ध पर बातचीत का महत्व भी व्यापक है। यदि तीनों देश तनाव घटाने की कोई साझा दिशा तलाशते हैं, तो पश्चिम एशिया में राहत की संभावना बन सकती है। लेकिन ईरान और अन्य प्रत्यक्ष पक्षों की भागीदारी के बिना स्थायी समाधान कठिन होगा। महाशक्तियां युद्धविराम के लिए वातावरण बना सकती हैं, संबंधित देशों की राजनीतिक इच्छा का स्थान नहीं ले सकतीं। किसी समझौते की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थिरता की चिंताओं को कितना संतुलित स्थान मिलता है।

यहीं एक बुनियादी प्रश्न उठता है: क्या विश्व व्यवस्था कुछ शक्तिशाली देशों के आपसी सौदों से संचालित होगी, अथवा व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहभागिता से? तीन देशों का संवाद स्वागतयोग्य है, लेकिन दूसरे देशों के भविष्य पर उनकी अनुपस्थिति में निर्णय लेने की प्रवृत्ति खतरनाक होगी। शांति की पहल तभी टिकाऊ बनती है जब प्रभावित समाज उसे स्वीकार करें। छोटे और मध्यम देशों की संप्रभुता किसी बड़ी रणनीतिक सौदेबाजी की मुद्रा नहीं हो सकती। भारत को इस सिद्धांत का स्पष्ट समर्थन करना चाहिए।

भारत के लिए पहला संभावित प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा का है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, होर्मुज से गुजरने वाले तेल के प्रमुख खरीदारों में भारत शामिल है। इसलिए पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और समुद्री परिवहन सामान्य होने से भारत को लाभ मिल सकता है। तेल की कीमतों तथा जहाजरानी और बीमा लागत में राहत आयात बिल और महंगाई के दबाव को घटा सकती है। लेकिन यह संभावित आर्थिक प्रभाव है, बैठक का सुनिश्चित परिणाम नहीं। वास्तविक लाभ युद्ध की स्थिति और आपूर्ति की बहाली पर निर्भर करेगा। दूसरा प्रश्न रणनीतिक संतुलन का है। अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत के संबंधों की प्रकृति अलग-अलग है। इनके बीच तनाव घटने से नई दिल्ली के लिए कूटनीतिक अवसर बढ़ सकते हैं। फिर भी भारत को देखना होगा कि किसी संभावित समझौते का हिंद-प्रशांत, सीमा सुरक्षा अथवा रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग पर क्या असर पड़ता है। महाशक्तियों के संबंध सुधरना अपने आप में भारत के विरुद्ध घटनाक्रम नहीं है। सही दृष्टिकोण प्रत्येक परिणाम को उसके वास्तविक प्रभाव के आधार पर परखना होगा।

तीसरा पहलू परमाणु संतुलन से जुड़ा है। भारत ने विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता और पहले प्रयोग न करने की नीति दोहराई है तथा सार्वभौमिक, सत्यापन योग्य और भेदभावरहित परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन किया है। इसी आधार पर भारत हथियार नियंत्रण की सार्थक पहल का स्वागत कर सकता है। लेकिन दक्षिण एशिया की सुरक्षा परिस्थितियों को अनदेखा करके उस पर कोई बाहरी ढांचा थोपना उचित नहीं होगा। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी भारतीय सुरक्षा चिंताओं को किसी व्यापक विमर्श में स्थान मिलना आवश्यक है।

चौथा प्रभाव आर्थिक प्रतिस्पर्धा में दिखाई दे सकता है। यदि अमेरिका और चीन के बीच स्थिरता बढ़ती है, तो वैश्विक व्यापार और निवेश को सहारा मिल सकता है। साथ ही, भारत को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि दोनों की प्रतिद्वंद्विता से उद्योग स्व